



उत्तराखण्ड सरकार

मुख्यमंत्री

श्री पुष्कर सिंह धामी

का

वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमानों

पर

बजट भाषण

आदरणीय अध्यक्ष जी,

1. आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं, देवभूमि उत्तराखण्ड के सभी देवी-देवताओं का स्मरण करते हुए, उत्तराखण्ड राज्य निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सभी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही, देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को मैं अपनी भावांजलि अर्पित करता हूँ।
2. मैं, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न परम श्रद्धेय स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी संपूर्ण सदन की ओर से नमन करता हूँ, जिन्होंने हम सभी का उत्तराखण्ड की स्थापना का स्वप्न साकार किया और विशेष औद्योगिक पैकेज देकर राज्य की नींव को मज़बूती प्रदान की।
3. मैं, उत्तराखण्ड राज्य की विकास यात्रा में अपना योगदान देने वाले सभी कर्मयोगियों को भी सादर प्रणाम करता हूँ।
4. इस पावन अवसर पर मैं, देवभूमि, तपोभूमि और वीरभूमि उत्तराखण्ड की दिव्य धरा का वंदन करते हुए, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूँ:

*“भू-लोक का गौरव,  
प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ,  
फ़ैला मनोहर गिरि हिमालय,  
और गंगाजल जहाँ।”*

5. अध्यक्ष जी, हम आभारी हैं कि हमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सतत स्नेह और निरंतर आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। जब भी हमारी देवभूमि किसी भीषण प्राकृतिक आपदा की घड़ी से गुज़री हो या किसी ऐतिहासिक एवं

गौरवशाली अवसर की साक्षी बनी हो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उत्तराखण्ड आकर हमारे मनोबल को दृढ़ किया है।

6. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन, रजत जयंती स्थापना दिवस, शीतकालीन यात्रा का शुभारंभ आदि प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड आगमन हम सबके लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत रहा है।
7. आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता से राष्ट्रीय महत्व की अनेक परियोजनायें उत्तराखण्ड में गतिमान हैं। इन परियोजनाओं तथा वर्ष पर्यन्त यात्राओं से आस्था, विकास एवं समृद्धि के एक नए स्वर्णिम अध्याय की ओर देवभूमि तेज़ी से अग्रसर है।
8. अध्यक्ष जी, आपदा के समय राहत एवं पुनर्वास के कार्यों में मिली उदार सहायता के लिए देवभूमि की जनता की ओर से, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराईयों से आभार व्यक्त करता हूँ।
9. अध्यक्ष जी, इस वर्ष हमने प्राकृतिक आपदा का विकराल रूप देखा। उत्तरकाशी में सिलाई बैण्ड, स्याना चट्टी, नौकैंची (बड़कोट), मोरी (ओडाटा), धराली; पौड़ी गढ़वाल में सैंजी, बुरांसी, बांकुडा; चमोली में थराली; रुद्रप्रयाग में छेनागाड़ व जखोली; बागेश्वर में ग्राम पौसारी कपकोट; देहरादून में कार्लीगाड़ (सहस्त्रधारा) सहित अनेक स्थानों में हमें प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा। प्राकृतिक आपदाओं में असमय मृत्यु को प्राप्त हुए दिवंगत आत्माओं को मैं श्रद्धांजली अर्पित करता हूँ।

10. अध्यक्ष जी, आपदा केवल भवन नहीं तोड़ती, लोगों के सपने, पीढ़ियों की कमाई और गाँवों की पहचान भी अपने साथ बहा ले जाती है। ऐसे समय में सरकार का पहला धर्म है कि तुरंत रेस्क्यू हो और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाये, बच्चों, बुजुर्गों को छत, भोजन, दवा और गरिमा के साथ आश्रय मिले।
11. इस सम्मानित सदन को अवगत कराना है कि आपदा प्रबन्धन करते हुए हमने न केवल पीड़ितों को आपदा से बाहर निकाला अपितु यह भरोसा भी दिया कि केन्द्र सरकार, हमारी राज्य सरकार व समाज सभी आपदा पीड़ितों के साथ खड़े हैं, वे अकेले नहीं हैं।
12. प्रतिकूल मौसम के बावजूद हमने अविलंब ग्राउंड जीरो में पहुंचने का प्रयास किया, रेस्क्यू अभियान की निगरानी की, केन्द्र सरकार की एजेंसी एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, आई0टी0बी0पी0 व सेना आदि से बहुमूल्य सहयोग प्राप्त किया तथा विभिन्न एजेंसियों एवं विभागों के मध्य समन्वय किया। हमने यथाआवश्यकता बड़े पैमाने पर हेली सेवाओं द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया।

*“हमने दर्द बांटा, हौसला बढ़ाया, राहत व अन्य सामग्री वितरण की,  
पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास के सुनियोजित प्रयास किये।”*

13. आदरणीय अध्यक्ष जी, 09 नवम्बर, 2000 को राज्य स्थापना के उपरांत राज्य की विकास यात्रा में “रजत जयंती” वर्ष 2025 का महत्वपूर्ण स्थान है। “रजत जयंती समारोह” के अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी के सम्बोधन के साथ विधानसभा का ‘विशेष सत्र’ आहूत किया गया, जिसमें राज्य की प्रगति एवं भविष्य के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा हुयी।

14. इसी क्रम में रजत जयंती दिवस 09 नवम्बर, 2025 को परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में 25 वर्ष की शानदार उपलब्धियों को साझा किया। इस अवसर पर अनेक महत्वपूर्ण भविष्यगामी योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया।
15. प्राकृतिक आपदाओं और आर्थिक चुनौतियों के बीच भी पिछले 25 वर्षों में हमने मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता व उद्यमियों की सक्रिय सहभागिता से विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं।
16. अध्यक्ष जी, इस वित्तीय वर्ष में हम दिव्य एवं भव्य कुम्भ के साक्षी बनेंगे। कुम्भ की विराटता अप्रतिम है। धर्म, आध्यात्म, ज्ञान-विज्ञान, भाषा, विचार एवं संस्कृतियों का समागम कुम्भ में होता है। कुम्भ में आध्यात्मिक चेतना विकसित होती है। इसी क्रम में श्रद्धालुओं की सुविधाओं, आधारभूत संरचना के सुदृढीकरण तथा सुव्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष प्राथमिकता के साथ आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
17. अध्यक्ष जी, हम शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा राज्य आंदोलनकारियों के महान योगदान को सदैव स्मरण में रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के उपरांत लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में लगभग 40 सड़कों के नाम अमर बलिदानी शहीदों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर किये हैं।
18. अध्यक्ष जी, हम राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखण्ड राज्य आंदोलन के दौरान शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों की पेंशन प्रतिमाह रुपये 3,000 से बढ़ाकर रुपये 5,500, विकलांग होकर पूरी तरह शय्याग्रस्त हुए आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह रुपये 20,000 से बढ़ाकर रुपये 30,000, सात दिन जेल गए अथवा राज्य आंदोलन के दौरान

घायल हुए राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह रूपये 6,000 से बढ़ाकर रूपये 7,000 तथा जेल गए या घायल श्रेणी से भिन्न अन्य राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन प्रतिमाह रूपये 4,500 से बढ़ाकर रूपये 5,500 किया जा चुका है।

19. अध्यक्ष जी, हमारे कार्यकाल में अनेक ऐसी उपलब्धियां हैं, जो प्रदेश के इतिहास में पहली बार दर्ज हुयी हैं। मैं सम्मानित सदन के समक्ष कुछ उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

- प्रदेश की जनता से किये गये वायदे को पूर्ण करते हुए 27 जनवरी, 2025 को पहली बार "समान नागरिक संहिता" (UCC) को लागू किया गया।
- पहली बार "सख्त-नकल विरोधी कानून" लागू करने वाला उत्तराखण्ड पहला राज्य बना।
- पहली बार, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम, 2025 प्रख्यापित किया है। इसी क्रम में दिनांक 01 जुलाई, 2026 से उत्तराखण्ड मदरसा बोर्ड अधिनियम, 2016 और उत्तराखण्ड अशासकीय अरबी एवं फारसी मदरसा मान्यता नियमावली 2019 निरस्त हो जायेंगे।
- पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का अवसर मिला और पहली बार ही पदक तालिका में उत्तराखण्ड शीर्ष 07 पदक विजेताओं में सम्मिलित हो सका एवं 100 से अधिक पदक उत्तराखण्ड को प्राप्त हुए।
- पहली बार अभूतपूर्व खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हुआ। पहली बार खेल विश्वविद्यालय बन रहा है।
- पहली बार राज्य गठन के बाद खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 6,500 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है।

- पहली बार वर्ष 2025–26 में राज्य के प्रतिष्ठित साहित्यकारों, भाषाविदों को दीर्घ कालीन साहित्य सेवा सम्मान (कुल 6 साहित्यकारों को 5–5 लाख रुपए की सम्मान राशि) से सम्मानित किया गया।
- पहली बार बहुप्रतीक्षित जमरानी, सौंग एवं लखवाड़ बांध परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए हमारी सरकार द्वारा कार्य किया गया तथा परियोजना का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- पहली बार बजट का आकार 1 लाख करोड़ से अधिक हुआ।
- पहली बार शीतकालीन यात्रा द्वारा वर्ष पर्यन्त, पर्यटन के विस्तार को नया आयाम दिया गया।
- पहली बार अवैध निर्माणों को चिन्हित करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्यवाही बड़े पैमाने पर हो रही है।
- पहली बार व्यापक पैमाने पर पौराणिक मंदिरों का सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है।
- पहली बार स्पिरिचुअल इकॉनामिक जोन के विकास के लिए सुनियोजित प्रयास किए जा रहे हैं।
- पहली बार हाई-अल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गयी है।
- पहली बार उत्तराखण्ड “सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लान्च” (जी0ई0पी0) करने वाला देश का पहला राज्य बना।
- पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी सतत् विकास लक्ष्य इंडेक्स में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर देश में उत्तराखण्ड ने शीर्ष स्थान हासिल किया।
- पहली बार भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल की उत्तराखण्ड राज्य में तैनात वाहिनी के लिए स्थानीय उत्पाद, जीवित बकरी, भेड़, कुक्कुट की आपूर्ति की जा रही है।

- पहली बार प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की वार्षिक संख्या 6 करोड़ के पार पहुंची है।

*हमने खाबों को हकीकत का लिबास पहनाया है,  
कर्तव्य पथ पर चलकर उपलब्धियों का अध्याय बनाया है।*

20. आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का कार्यकाल अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियों का साक्षी रहा है। इस वर्ष भी हमारी सरकार की उपलब्धियों को सराहा गया है। मैं यहाँ कुछ उपलब्धियों का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- उद्योग विभाग के सुधारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एण्ड इंटरनल ट्रेड (डी0पी0आई0आई0टी0) के बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (बी0आर0ए0पी0) 2024 में राज्य को “टॉप अचीवर्स” श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ, जो शासन- प्रक्रियाओं में सुधार तथा निवेश-अनुकूल माहौल का द्योतक है।
- प्राथमिक 23 डी-रेगुलेशन क्षेत्रों के क्रियान्वयन में राज्य ने 5वीं रैंक प्राप्त की, जिससे उत्तराखण्ड “बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स” में उभर कर सामने आया है।
- लॉजिस्टिक ईज एक्रास डिफरेंट स्टेट (लीड्स) 2024 में राज्य को टॉप अचीवर्स श्रेणी में मान्यता मिली, जो प्रदेश में लॉजिस्टिक नेटवर्क एवं कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए लागू सुधारों का सकारात्मक परिणाम है।
- नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स (ई0पी0आई0) 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखण्ड प्रथम रैंक पर रहा, जो निर्यात संवर्धन प्रयासों की सफलता तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि को दर्शाता है।

- उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (यूकाडा) को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन द्वारा एविएशन इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने हेतु “सर्वश्रेष्ठ राज्य” का पुरस्कार प्रदान दिया गया।

21. हम सिर्फ घोषणा करने पर यकीन नहीं करते हैं अपितु यह सुनिश्चित करते हैं कि घोषणाओं का क्रियान्वयन हो।

*जो कहा वो करेंगे, ये हमारी पहचान है।*

इसलिए अनेक ऐसी परियोजनाएं जिनका मैंने शिलान्यास किया था, उनका लोकार्पण भी मेरे द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री के रूप में की गयी 3885 घोषणाओं में 2408 में शासनादेश निर्गत हो गये हैं तथा 995 घोषणाओं में कार्यवाही गतिमान है।

*यूं ही नहीं आपको लोकार्पण के शिलापट दिखते हैं,*

*हम घोषणाओं को कर्म की स्याही से लिखते हैं।*

22. आदरणीय अध्यक्ष जी, हमने अपने पिछले बजट भाषणों में सैचुरेशन लक्ष्यों का उल्लेख किया था। सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए हर्ष होता है कि:—

हमने असुरक्षित पुल व ट्राली के सुरक्षित विकल्प प्रदान करने, सभी जनपदों में हवाई सम्पर्क सुविधा देने, सरकारी विद्यालयों में आवश्यक फर्नीचर की आपूर्ति करने, ई-ऑफिस क्रियान्वयन, जनपद मुख्यालय एवं 50 हजार से अधिक आबादी वाले शहरों में पुस्तकालय, इण्डोर तथा ओपन स्टेडियम, थीम बेस्ड विज्ञान व नवाचार केन्द्र तथा ऑडिटोरियम और संस्कृति केन्द्र की स्थापना एवं सुदृढीकरण में लगभग सैचुरेशन की स्थिति को प्राप्त कर लिया है।

23. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस दशक को “उत्तराखण्ड का दशक” बनाने के लिए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूर्ण किये जा चुके हैं। हम “संकल्प से सिद्धि की ओर” निरंतर अग्रसर हैं। उत्तराखण्ड को

एक समृद्ध एवं सुरक्षित राज्य के रूप में स्थापित करना हमारा “विकल्प रहित संकल्प” है।

24. अध्यक्ष जी, हम इस “संकल्प” (SANKALP) को जनादेश मानते हुए होलिस्टिक एप्रोच के साथ काम कर रहे हैं। हम समग्र विकास (S), आत्मनिर्भरता (A), नवाचार (N), कौशल विकास (K), अवसंरचना विकास (A), लोक-सहभागिता (L), पारदर्शिता (P) को मार्गदर्शक सिद्धांत मानकर “विकल्प रहित संकल्प” को पूर्ण करने की दिशा में सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं।

25. माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट हमारी सरकार की दृष्टि और रणनीति की निरंतरता को दर्शाता है। हमने पिछले बजट भाषणों में गरीब, युवा, अन्नदाता, और नारी सशक्तिकरण की अवधारणा के साथ “ज्ञान” (GYAN) पर फोकस किया था।

सम्मानित सदन को यह अवगत कराना है कि यह बजट “ज्ञान” – गरीब, युवा, अन्नदाता, और नारी सशक्तिकरण की मूल धारणा के साथ-साथ “विज्ञान” का (VIGYAN) का बजट है।

“विज्ञान” (VIGYAN) से आशय है— वेल्यू बेस्ड (V), इनोवेशन ड्रिवन (I), गुड गवर्नेंस (G), यूथ-पावर्ड (Y) और एकाउंटेबिलिटी (A) की मूल अवधारणा पर निर्मित नया उत्तराखण्ड (N)।

26. अध्यक्ष जी, यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज़ नहीं, लगभग सवा करोड़ उत्तराखण्डवासियों का विकास-संकल्प है। यह बजट *सर्वस्पर्शी, नवोन्मेषी और सर्वांगीण है। यह गाँव और शहर, गरीब और समृद्ध, किसान और वैज्ञानिक, परंपरा और आधुनिकता, को ध्यान में रखते हुए, विकसित उत्तराखण्ड के मार्ग को प्रशस्त करेगा।*

27. इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बजट के माध्यम से विभिन्न विभागों के अन्तर्गत अनेक नयी योजनाओं को प्रारंभ किया गया है तथा विद्यमान योजनाओं में

समुचित बजट प्रावधान किये गये हैं। इस तथ्य का विशेष ध्यान रखा गया है कि बजट "संतुलित" हो।

28. आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बजट का मुख्य उद्देश्य—

*“नई सोच और नवाचार के साथ,  
लोक-सहभागिता को प्रोत्साहित कर न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करते हुए,  
गांव व शहर को उन्नत बनाकर और तीव्र विकास द्वारा,  
आत्म-निर्भर उत्तराखण्ड की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए,  
आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित होना और  
समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।”*

29. अध्यक्ष जी, इसी सोच के साथ इस बजट को आगामी अंशों में अंग्रेजी भाषा के आठ एल्फाबेट्स S,A,N,T,U,L,A,N (संतुलन) यानि समावेशी, आत्मनिर्भर, नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक-सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था से समझाने का विनम्र प्रयास किया है।

30. समावेशी विकास हमारा अडिग संकल्प है। ऐसा विकास जिसमें सबके लिए अवसर और सम्मान हो। इसी क्रम में "संतुलन" (SANTULAN) के पहले एल्फाबेट "S" अर्थात् समावेशी विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ—

किसी भी सर्वस्पर्शी सरकार की पहचान इस बात से होती है कि वह अपने सबसे कमजोर, सबसे वंचित और सबसे ज़रूरतमंद नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करता है। हमारी सरकार ने "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" की भावना के साथ सामाजिक सुरक्षा को राज्य नीति का केन्द्रीय स्तंभ बनाया है।

- हमने निर्धन, बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग, अकेली माता आदि को "दया के पात्र" नहीं, बल्कि "अधिकार के पात्र" मानते हुए योजनाएँ बनाई हैं।
- वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित लगभग साढ़े नौ लाख पेंशनरों को प्रत्येक माह नियमित आधार पर पेंशन दी जा रही है। इस बजट में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में समग्र रूप से लगभग रुपये एक हजार तीन सौ सत्ताईस करोड़ तिहत्तर लाख (रु0 1327.73 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- आयुष्मान भारत और अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के तहत निःशुल्क, कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है, जिससे कोई गरीब सिर्फ़ पैसे के अभाव में इलाज से वंचित न रहे। जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि "इलाज तो लाखों का था, लेकिन योजना की वजह से परिवार बच गया", तब हमें अपने निर्णयों की वास्तविक सफलता दिखाई देती है। इस बजट में अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना हेतु रुपये छः सौ करोड़ (रु0 600.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

31. अध्यक्ष जी, इसी क्रम में सम्मानित सदन के सामने समावेशी विकास के द्योतक गरीब कल्याण को समर्पित कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख किया जा रहा है:-

- राज्य खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत रुपये पच्चीस करोड़ (रु0 25.00 करोड़), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये दो सौ अठानवे करोड़ पैंतीस लाख (रु0 298.35 करोड़), प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) हेतु समग्र रूप से लगभग रुपये छप्पन करोड़ बारह लाख (रु0 56.12 करोड़), ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों हेतु अनुदान के अन्तर्गत रुपये पच्चीस करोड़ (रु0 25.00 करोड़), परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी

के यात्रियों हेतु निःशुल्क यात्रा की सुविधा हेतु रूपये बयालीस करोड़ (रू0 42.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

32. महिला समानता को प्रोत्साहित करने एवं जेण्डर संवेदनशील प्लानिंग के लिए जेण्डर बजटिंग महत्वपूर्ण है। वित्तीय वर्ष 2025–26 में जेण्डर बजट में रूपये सोलह हजार नौ सौ इकसठ करोड़ बत्तीस लाख (रू0 16,961.32 करोड़) का प्रावधान किया गया था। इस वर्ष जेण्डर बजटिंग में उन्नीस हजार छः सौ बयानवे करोड़ दो लाख (रू0 19,692.02 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

- सक्षम आंगनबाड़ी एण्ड पोषण 2.0 योजना के अन्तर्गत 06 माह से 06 वर्ष के लगभग सात लाख तैंतीस हजार लाभार्थियों को अनुपूरक पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रूपये पांच सौ अठानवे करोड़ तैंतीस लाख (रू0 598.33 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- महिलाओं एवं बच्चों के पोषण स्तर में और अधिक सुधार करने तथा पोषण सम्बन्धी जागरूकता जन-जन तक पहुंचाने हेतु प्रधानमंत्री पोषण मिशन हेतु समग्र रूप से लगभग रूपये एक सौ उन्चास करोड़ पैंतालीस लाख (रू0 149.45 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से लगभग रूपये चौदह करोड़ तेरह लाख (रू0 14.13 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना हेतु रूपये तीस करोड़ (रू0 30.00 करोड़), मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना हेतु रूपये पच्चीस करोड़ (रू0 25.00 करोड़), मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना हेतु रूपये पन्द्रह करोड़ (रू0 15.00 करोड़), मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना हेतु रूपये पन्द्रह करोड़ (रू0 15.00 करोड़), मुख्यमंत्री महिला पोषण योजना हेतु लगभग रूपये तेरह करोड़ चौवालीस लाख

(रु० लगभग 13.44 करोड़), मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु रूपये आठ करोड़ (रु० 8.00 करोड़) और निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए रूपये पांच करोड़ (रु० 5.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

33. अध्यक्ष जी, समावेशी विकास के दृष्टिकोण से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर किया गया निवेश भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अवसंरचना का विकास किया जा रहा है। इस क्रम में बागेश्वर में जिला चिकित्सालय; देहरादून में उप जिला चिकित्सालय, डोईवाला, उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बालावाला; उत्तरकाशी में उप जिला चिकित्सालय, भटवाड़ी; हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय, भगवानपुर; अल्मोड़ा में उप जिला चिकित्सालय, चौखुटिया; पौड़ी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दुगड़डा; टिहरी गढ़वाल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पिलखी तथा नैनीताल में मल्टीस्पेशियलिटी- सुपरस्पेशियलिटी अस्पताल, भवाली सहित अनेक योजनाओं पर कार्यवाही गतिमान है।

- आगामी वित्तीय वर्ष हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ग्रांट के अन्तर्गत समग्र रूप से राजस्व मद में लगभग रूपये चार हजार दो सौ बावन करोड़ पचास लाख (रु० 4252.50 करोड़) तथा पूंजीगत मद में लगभग रूपये एक सौ पिचानवे करोड़ छियालिस लाख (रु० 195.46 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

34. अध्यक्ष जी,

- समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए 'अनुसूचित जातियों के कल्याण' ग्रांट के अन्तर्गत लगभग रूपये दो हजार चार सौ अड़सठ करोड़ नवासी लाख (रु० 2468.89 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

- 'अनुसूचित जनजातियों के कल्याण' ग्रांट के अन्तर्गत समग्र रूप से लगभग रूपये सात सौ छियालीस करोड़ सतहत्तर लाख (रू0 746.77 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत पूंजीगत मद में रूपये अठानवे करोड़ पैंतीस लाख (रू0 98.35 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

35. अध्यक्ष जी, "संतुलन" (SANTULAN) के दूसरे एल्फाबेट "A" अर्थात् आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड बनाने के संदर्भ में कृषि, उद्योग और पर्यटन इन तीनों क्षेत्रों की क्षमता को एक साथ आगे बढ़ाते हुए हम ऐसा परिवेश निर्मित कर रहे हैं, जिसमें उत्पादकता बढ़े, निवेश आकर्षित हो और सम्मानजनक आजीविका के अवसर मिलें।

- आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण के लिए कृषि, उद्यम और पर्यटन प्रत्येक सेक्टर को अपनी भूमिका मज़बूती से निभानी होगी। हमारे अन्नदाता हमारी शक्ति हैं।
- हम गंभीरतापूर्वक प्रयास कर रहे हैं कि अन्नदाता किसान को आवश्यक सहयोग, आधुनिक तकनीक, बेहतर बाज़ार और मज़बूत अवसंरचना मिले; उद्योग-व्यापार को ऐसा अनुकूल वातावरण मिले जहाँ उत्पादन और रोजगार दोनों बढ़ें और पर्यटन के क्षेत्र में हमारी प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक धरोहर नई ऊर्जा के साथ विश्व-पटल पर उभरे।

36. अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता की इस यात्रा में कृषि, उद्योग और पर्यटन हमारे तीन ग्रोथ ड्राइवर्स हैं। ये विकास इंजन मिलकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देंगे, रोजगार के अवसर बढ़ाएँगे और हर नागरिक के जीवन में समृद्धि तथा आत्मविश्वास की नई शक्ति भरेंगे।

- हम कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न नीतियों जैसे डेयरी विकास, एप्पल मिशन तथा "स्कीम फॉर अपग्रेडेशन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट एप्पल लॉजिस्टिक (सुफल)", उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन, फल-सब्ज़ी प्रसंस्करण, पुष्प,

औषधीय पौधों के उत्पादन तथा जैविक खेती आदि के माध्यम से प्रति इकाई आय बढ़ाने पर कार्य कर रहे हैं।

- स्थानीय उत्पादों को सीधे बाज़ार से जोड़ा जा रहा है, ताकि उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो सके। "मिलेट मिशन" के माध्यम से पोषण सुरक्षा और किसानों की आय दोनों में सुधार सुनिश्चित किया जा रहा है।

37. अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड की विकास यात्रा के इस क्रम में "हाउस ऑफ हिमालयाज़" का उल्लेख करना चाहूंगा। "वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल" की सोच पर आधारित यह पहल विशेष रूप से महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों की आय बढ़ाने, पलायन रोकने, और पहाड़ में ही सम्मानजनक रोजगार एवं उद्यमिता के अवसर बनाने के उद्देश्य से डिजाइन की गई है।

आज "हाउस ऑफ हिमालयाज़" देवभूमि के स्थानीय उत्पादों को एक एकीकृत ब्रांड के रूप में सामने लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम कर रही है।

- उत्तराखण्ड महक क्रान्ति नीति 2026-36 का शुभारंभ किया गया है। इस बजट में महक क्रान्ति हेतु रूपये दस करोड़ (₹10.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

38. अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन के सामने कृषि व संबंधित गतिविधियों के संबंध में किये जा रहे कुछ बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- समग्र रूप से पूंजीगत मद में पशुपालन विभाग के अन्तर्गत रूपये सैतालीस करोड़ (₹47.00 करोड़), मत्स्य विभाग के अन्तर्गत लगभग रूपये तीस करोड़ तेरह लाख (₹30.13 करोड़), औद्योगिक विकास विभाग के अन्तर्गत रूपये चौहत्तर करोड़ (₹74.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ हेतु रूपये बीस करोड़ (₹20.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

- समग्र रूप से मिशन एप्पल के लिए रूपये बयालीस करोड़ (रु0 42.00 करोड़), उच्च मूल्य वाले फलों (कीवी, ड्रेगन फ्रूट आदि) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लगभग रूपये तीस करोड़ सत्तर लाख (रु0 30.70 करोड़), राज्य में चाय विकास योजना के लिए लगभग रूपये पच्चीस करोड़ तिरानवे लाख (रु0 25.93 करोड़), सगन्ध पौधा केन्द्र को अनुदान एवं सगन्ध पौधों के कलस्टर विकास के लिए लगभग रूपये चौबीस करोड़ पिचहत्तर लाख (रु0 24.75 करोड़), उद्यान बीमा योजना हेतु रूपये चालीस करोड़ (रु0 40.00 करोड़), मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना हेतु रूपये बीस करोड़ (रु0 20.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- पशुपालन विभाग के अन्तर्गत स्वरोजगारपरक व लाभार्थीपरक योजना हेतु लगभग रूपये बयालीस करोड़ दो लाख (रु0 42.02 करोड़), मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हेतु रूपये बारह करोड़ तैंतालीस लाख (रु0 12.43 करोड़), ट्राउट प्रोत्साहन योजना (FIDF) हेतु लगभग रूपये उन्तालीस करोड़ नब्बे लाख (रु0 39.90 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

39. अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भरता के लिए कृषि के साथ— साथ उद्योग भी महत्वपूर्ण है। राज्य में सीमित भूमि उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार, देहरादून (सेलाकुई) और ऊधमसिंह नगर (काशीपुर, किच्छा एवं पंतनगर) में "फ्लैटेड फैक्ट्री" का निर्माण किया जा रहा है, जिनके माध्यम से लगभग 43 हजार वर्गमीटर प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध होगा।

एम0एस0एम0ई0, स्टार्ट-अप, सेवा-क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में लिए गये नीतिगत निर्णयों से निवेश और स्थानीय भागीदारी दोनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उभरते हुए स्टार्ट-अप से युवाओं के लिए रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर तेज़ी से बढ़ रहे हैं।

40. अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन के सामने उद्योग से संबंधित योजनाओं में किये गये बजट प्रावधानों का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- मेगा इंडस्ट्रियल एवं मेगा टेक्सटाईल नीति के तहत अनुदान के लिए रूपये पच्चीस करोड़ (रु0 25.00 करोड़), महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना के लिए रूपये चार करोड़ (रु0 4.00 करोड़), प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को सहायता योजना के लिए रूपये पिचहत्तर करोड़ (रु0 75.00 करोड़), मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए रूपये साठ करोड़ (रु0 60.00 करोड़), प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप और इंटरप्रीनियोरशिप के लिए रूपये तीस करोड़ (रु0 30.00 करोड़) तथा स्टार्ट अप वेंचर फंड हेतु रूपये पच्चीस करोड़ (रु0 25.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

41. अध्यक्ष जी, आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के लिए कृषि और उद्योग पर संक्षिप्त चर्चा के उपरांत अब मैं पर्यटन सेक्टर की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ:-

देवभूमि उत्तराखण्ड में आस्था, साहसिक पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का अद्वितीय संगम है, इसलिए हमारी सरकार ने पर्यटन को विशेष प्राथमिकता दी है। उत्तराखण्ड नैसर्गिक रूप पर्यटक प्रदेश है।

*देवों की धरा, हिमालय का द्वार,*

*माथे पे तिलक, सुंदर अपार।*

42. अध्यक्ष जी, आगामी वित्तीय वर्ष में “मानसखण्ड मंदिर माला मिशन योजना” के अन्तर्गत द्वितीय चरण में 14 मंदिरों के सुदृढीकरण तथा “केदारखण्ड माला मिशन” के अन्तर्गत में केदारखण्ड के महत्वपूर्ण मंदिर केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रूद्रनाथ, कल्पेश्वर इत्यादि मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

- टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान के अन्तर्गत महासू देवता हनोल, भारत के प्रथम गांव माणा, टिम्मरसेण चमोली, गुंजी पिथौरागढ़ का विकास किया जा रहा है।

- वाइब्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के जादुंग में अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही हैं।
- सड़कों, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता और होम-स्टे जैसी सुविधाओं को एकीकृत दृष्टि से विकसित किया जा रहा है, ताकि "सुरक्षित, सुगम और स्वच्छ धार्मिक यात्रा" का नया मॉडल स्थापित हो सके।
- "सस्टेनेबल टूरिज्म" के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ होमस्टे, इको-टूरिज्म, ट्रेकिंग ट्रेल्स, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स और वेलनेस टूरिज्म, योग-केंद्र व फिटनेस अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके सम्मिलित प्रभाव से उत्तराखण्ड "ऑल-सीज़न डेस्टिनेशन" के रूप में स्थापित हो रहा है।
- हमारा प्रयास है कि विकास-मॉडल पर्यावरण संरक्षण और जलवायु-संवेदनशीलता पर आधारित हो। इस सम्बन्ध में नई सोच यह है कि जंगल, जल, मिट्टी और जैव-विविधता को भविष्य की पूँजी मानकर हर योजना को डिजाइन किया जाए।
- अध्यात्म, योग, आयुर्वेद और लोक-संस्कृति के इन पारंपरिक क्षेत्रों को आधुनिक वेलनेस-इकोनॉमी के साथ जोड़ते हुए वैश्विक पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इस बजट में वैश्विक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु रूपये दस करोड़ (₹ 10.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए समग्र रूप से रूपये अट्ठारह करोड़ पचास लाख (₹ 18.50 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन हेतु रूपये दो करोड़ (₹ 2.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

- समग्र रूप से पर्यटन विभाग के अन्तर्गत राजस्व मद में रूपये दो सौ दस करोड़ उनसठ लाख (रू0 210.59 करोड़) तथा पूंजीगत मद में लगभग रूपये दो सौ छियानवे करोड़ पैतालीस लाख (रू0 296.45 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

43. अध्यक्ष जी, नवाचार हमारी ताकत है। हम नए विचारों, नई तकनीक और नए तरीकों को अपनाकर शासन को अधिक सरल, अधिक पारदर्शी और अधिक मानवीय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उत्तराखण्ड आज नई सोच और नवाचार को विकास का मुख्य आधार बनाकर आगे बढ़ रहा है।

*पुरानी समस्याओं के लिए पुराने समाधान नहीं,*

*बल्कि समयानुकूल, रचनात्मक और साहसी कदम उठाना हमारी कार्य शैली है।*

इसी क्रम में “संतुलन” (SANTULAN) के तीसरे एल्फाबेट “N” अर्थात् नई सोच के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत अनेक नवाचार हो रहे हैं। प्रसंगवश उन नवाचारों का उल्लेख अन्यत्र भी इस बजट भाषण में किया गया है।

मैं, नई सोच और नई तकनीक के प्रतीकस्वरूप किये जा रहे कुछ प्रयासों की ओर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ:

सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और गति के लिए ई-ऑफिस जैसा नवाचार आज प्रदेश के 865 कार्यालयों में लागू हो चुका है। पहले अधिकांश सेवाएँ ऑफलाइन मिलती थीं, जबकि अब “अपणि सरकार पोर्टल” के माध्यम से 78 विभागों की 975 नागरिक केन्द्रित सेवाएं विकसित एवं एकीकृत है। स्थायी निवास, जाति, आय और रोजगार पंजीकरण से जुड़े लगभग 1.17 करोड़ से अधिक प्रमाण-पत्र जारी हो चुके हैं।

44. अध्यक्ष जी, नई सोच का एक सशक्त उदाहरण यह है कि हम युवाओं के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण, स्पोर्ट्स एवं कौशल विकास आदि के लिए आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

*“देव कृपा से पास हमारे  
घने जंगल, निर्मल जल  
इसके साथ हमारी शक्ति  
हमारे युवाओं का आत्मबल।*

- इसी के क्रम में “देवभूमि उद्यमिता योजना” उत्तराखण्ड का उल्लेख कर रहा हूँ। इस योजना से कॉलेज-कैंपस को ही नवाचार और स्टार्ट-अप की प्रयोगशाला बनाया गया है। हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी सिर्फ नौकरी-प्रार्थी नहीं, बल्कि नौकरी-दाता और नवप्रवर्तक बनकर उभरे।
- इस योजना अन्तर्गत 300 से ज्यादा छात्रों ने अपना क्वालिटी स्टार्टअप शुरू किया है। 20 स्टूडेंट स्टार्टअप को सीड फण्ड सहयोग दिया गया है। 1240 विद्यार्थियों ने अपने उद्यमों का औपचारिक पंजीकरण किया है। विद्यार्थियों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग सहायता प्रदान की जा रही है। कई विद्यार्थियों ने पेटेंट हेतु भी आवेदन किया है।
- देवभूमि उद्यमिता केवल योजना नहीं, बल्कि युवाओं को “नई सोच, जोखिम लेने का साहस तथा तकनीक” से जोड़ने वाला व्यापक आंदोलन है।
- अध्यक्ष जी, तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत इमर्जिंग टैक्नोलाजी प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है। देहरादून, रानीपोखरी, नरेन्द्रनगर, श्रीनगर, द्वाराहाट, नैनीताल, काशीपुर एवं लोहाघाट के पॉलिटैक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत लगभग 5 हजार छात्र आधुनिक प्रशिक्षण से लाभान्वित हो रहे हैं।
- नई सोच के इस क्रम को बढ़ाते हुए तकनीकी शिक्षा विभाग के संकाय सदस्यों एवं छात्र-छात्राओं को आई0आई0टी0 दिल्ली, जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में एक्सपोजर विजिट की अभिनव पहल हमने की है।

- छात्रों की इम्प्लोएबिलिटी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक अभिनव पहल के रूप में इस बजट में “मुख्यमंत्री हब एवं स्पोक मॉडल” प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसमें पॉलिटेक्निक, आई0टी0आई0, उच्च शिक्षण संस्थान एवं माध्यमिक शिक्षा के संस्थानों को एकीकृत किया जायेगा।
- राज्य के स्वयं के राजस्व में वृद्धि के लिए प्रवर्तन-कार्रवाई के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी की सहायता भी ली जा रही है। खनन और भू-संसाधन क्षेत्र में “माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड सर्विलांश सिस्टम” (एमडीटीएसएस) के माध्यम से ड्रोन, सीसीटीवी, डिजिटल गेट और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर अवैध खनन पर नियंत्रण और राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित की जा रही है। खनन सर्विलांश योजना के अन्तर्गत लगभग रूपये चौबीस करोड़ पचास लाख (रु0 24.50 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में “लैब ऑन व्हील्स” जैसी पहल से दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों के बच्चों तक विज्ञान प्रयोगशालाएँ सीधे पहुँच रही हैं। आज प्रत्येक जनपद में “लैब ऑन व्हील्स” है। इस योजना के अधिक विस्तार के लिए आगामी बजट में रूपये चार करोड़ (रु0 4.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- अध्यक्ष जी, हमने उच्च शिक्षा विभाग में अध्ययनरत छात्रों के एक्सपोजर विजिट के लिए भारत दर्शन योजना की अभिनव पहल शुरू की है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आगामी बजट में हम उत्तराखण्ड दर्शन के लिए भी एक नई योजना ला रहे हैं।
- हमने दून विश्वविद्यालय में हिंदू अध्ययन केन्द्र के लिए पद सृजित करने का निर्णय लिया है।

- राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए नई खेल नीति लागू की गयी है। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अन्तर्गत 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वर्ग में प्रति जनपद चयनित 300 छात्र-छात्राओं को रू0 1,500 प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
- मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 14 वर्ष से 23 वर्ष की आयु वर्ग के चयनित प्रति जनपद 200 खिलाड़ियों और इस प्रकार कुल 2600 छात्र-छात्राओं को रू0 2,000 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।
- उद्यमिता, कौशल एवं नवाचार योजना के अन्तर्गत लगभग रूपये सात करोड़ ग्यारह लाख (रू0 7.11 करोड़), दून लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेंटर को अनुदान हेतु रूपये सात करोड़ साठ लाख (रू0 7.60 करोड़), राजकीय महाविद्यालयों में ई-ग्रंथालय की स्थापना हेतु रूपये सात करोड़ (रू0 7.00 करोड़), शोध एवं विकास कार्य योजना हेतु रूपये एक करोड़ (रू0 1.00 करोड़), विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु रूपये पन्द्रह करोड़ (रू0 15.00 करोड़), उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु रूपये पन्द्रह करोड़ (रू0 15.00 करोड़) तथा खेल विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति हेतु लगभग रूपये तेरह करोड़ पचास लाख (रू0 13.50 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

45. अध्यक्ष जी, समग्र रूप से पूंजीगत मद में- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रूपये पांच सौ बयालीस करोड़ चौरासी लाख (रू0 542.84 करोड़), उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत रूपये एक सौ छियालीस करोड़ तीस लाख (रू0 146.30 करोड़), तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत लगभग रूपये अठानवे करोड़ पचास लाख (रू0 98.50 करोड़), खेल विभाग के अन्तर्गत लगभग रूपये उन्हत्तर करोड़ चौरानवे लाख (रू0 69.94 करोड़), कला एवं संस्कृति विभाग के अन्तर्गत लगभग रूपये नौ करोड़ नब्बे लाख (रू0 9.90 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

46. सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रूपये छियासी करोड़ (रू0 86.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

47. संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान हेतु रूपये अट्ठाईस करोड़ (रू0 28.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

48. अध्यक्ष जी, नई सोच के प्रतीक कुछ अन्य योजनाओं का यहां उल्लेख किया जा रहा है:-

- शहरी क्षेत्रों में पैदल मार्ग अवसंरचना के अन्तर्गत रूपये दस करोड़ (रू0 10.00 करोड़), नगर निकायों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने हेतु रूपये तीस करोड़ (रू0 30.00 करोड़), राज्य डॉटा सेंटर सुदृढीकरण के लिए समग्र रूप से रूपये पैंसठ करोड़ (रू0 65.00 करोड़), विज्ञान धाम के अन्तर्गत लगभग रूपये छः करोड़ पचानवे लाख (रू0 6.95 करोड़), इमरजिंग टेक्नोलॉजी एवं ए0आई0 (सी0ओ0ई0) के क्रियान्वयन हेतु लगभग रूपये दस करोड़ पचास लाख (रू0 10.50 करोड़), साइबर सिक्योरटी के क्रियान्वयन हेतु रूपये पन्द्रह करोड़ (रू0 15.00 करोड़), पैक्स के कम्प्यूटरीकरण हेतु लगभग रूपये पांच करोड़ सड़सठ लाख (रू0 5.67 करोड़), जनपदों में केंद्रीकृत रिकॉर्ड रूम के अन्तर्गत रूपये दस करोड़ (रू0 10.00 करोड़), सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के अन्तर्गत लगभग रूपये सैंतालीस करोड़ पचास लाख (रू0 47.50 करोड़), यूनीफार्म सिविल कोड के अन्तर्गत रूपये पांच करोड़ (रू0 5.00 करोड़), संशोधित आईपीसी, सीआरपीसी एवं साक्ष्य अधिनियम हेतु प्रशिक्षण के अन्तर्गत रूपये पांच करोड़ (रू0 5.00 करोड़), विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अन्तर्गत रूपये छः करोड़ इकहत्तर लाख (रू0 6.71 करोड़), संघ लोक सेवा आयोग एवं उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षाओं की कोचिंग हेतु मेधावी छात्र एवं छात्राओं को विशेष आर्थिक सहायता के अन्तर्गत रूपये एक करोड़ पचास लाख (रू0 1.50 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

49. अध्यक्ष जी, ऐसे अनेक और प्रावधान इस बजट में हैं। ये प्रावधान एक नये अवसरयुक्त परिवेश के द्योतक हैं। प्रसिद्ध कवि श्री शिव मंगल सिंह सुमन जी की पंक्तियों के साथ युवाओं को इन नये अवसरों का लाभ लेने का आह्वान कर रहा हूँ:

गति प्रबल पैरों में भरी,  
फिर क्यों रहूँ दर-दर खड़ा,  
जब आज मेरे सामने  
है रास्ता इतना पड़ा।

जब तक न मंजिल पा सकूँ  
तब तक मुझे न विराम है,  
चलना हमारा काम है।

50. अध्यक्ष जी, हमारा यह विश्वास है कि राज्य के परम वैभव की प्राप्ति हेतु संस्कृति के संवर्द्धन को प्राथमिकता में रखना होगा। उत्तराखण्ड के गौरव कवि सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्तियों का स्मरण कर रहा हूँ:-

“प्रखर बुद्धि से भले,  
सभ्यता हो नव निर्मित,  
संस्कृति के निर्माण के लिए हृदय चाहिए”

51. हमारा मानना है कि विकसित उत्तराखण्ड अपनी पहचान अपनी भाषा, लोक-कला, संस्कृति और अध्यात्म की नवाचारी प्रस्तुति से भी बनाए। लोक-संस्कृति, लोक-संगीत, लोक-नृत्य और लोक-कथाएँ हमारी विशिष्टता है। इन परंपराओं को सिर्फ मंच पर नहीं, बल्कि डिजिटल माध्यमों एवं नवाचारी कार्यक्रमों वाली पहलों के जरिए अगली पीढ़ी से जोड़ने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। इस हेतु रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन और डिजिटल आर्काइव जैसे नवाचारी माध्यमों के प्रयोग की कार्यवाही गतिमान हैं।

52. अध्यक्ष जी, सम्मानित सदन को अवगत कराना है कि इस बजट में संस्कृति विभाग के अन्तर्गत पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए बजट प्रावधान किया गया है।

इसी नवाचारी सोच के क्रम में आज प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना हो चुकी है। इस बजट में संस्कृत ग्राम के संचालन हेतु रूपये एक करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

53. भाषा विभाग, उत्तराखण्ड की लोकभाषाओं और बोलियों जैसे गढ़वाली, कुमाँऊनी, जौनसारी एवं अन्य लुप्तप्राय बोलियों को संरक्षित करने, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार, बहु-विषयी बनाने के साथ विज्ञान और शिक्षा के साथ जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार की योजना "भाषिणी" एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे तकनीकी नवाचार की कार्ययोजना पर विषय विशेषज्ञों एवं भाषाविदों के साथ कार्यवाही कर रहा है।

54. अध्यक्ष जी, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रदेशवासियों के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। इस सम्बन्ध में प्रभावितों को राहत पहुँचाने के दृष्टिगत हमने मानव वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को दी जाने वाली धनराशि को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया है।

- एक अभिनव पहल के अन्तर्गत हम कैम्पा निधि के अन्तर्गत पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, उधमसिंहनगर एवं बागेश्वर में प्रति ट्रांजिट सेन्टर 2 करोड़ के संभावित व्यय के आधार पर 14 करोड़ की धनराशि का प्रावधान कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एनीमल रेस्क्यू सेन्टर के संचालन हेतु 5 करोड़ की धनराशि भी कैम्पा निधि के अन्तर्गत प्रावधानित की गयी है।
- वन विभाग के अन्तर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रूपये एक सौ इकत्तीस करोड़ अड़सठ लाख (रु० 131.68 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

55. अध्यक्ष जी, अब मैं “संतुलन” (SANTULAN) के चौथे एल्फाबेट “T” अर्थात् तीव्र विकास के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:-

हमारी सरकार ने अवस्थापना विकास को प्राथमिकता दी है। हमारा यह विश्वास है कि किसी भी राज्य के विकास की रीढ़ उसकी अवसंरचना होती है। तीव्र विकास के लिए हमारा यह संकल्प है कि प्रदेश की सड़क, ऊर्जा तथा आधुनिक अवसंरचना को नई गति और नई दिशा दी जाए।

56. अध्यक्ष जी, हमने पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर अवसंरचना में निवेश बढ़ाया है, जो आने वाले वर्षों में सतत विकास की नींव को और मजबूत करेगा। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा लगभग ₹0 5 हजार करोड़ था, जो पिछले दो वित्तीय वर्षों में लगभग ₹0 11 हजार करोड़ हो गया है। इस वर्ष भी हम पूर्व वर्षों की तुलना में अधिक पूंजीगत व्यय करने की दिशा में बढ़ रहे हैं।

*“जहाँ सड़क पहुँचती है,  
वहाँ अवसर पहुँचते हैं;  
वहाँ भविष्य पहुँचता है।”*

57. पहाड़ों में सुरंगों, पुलों और आधुनिक ढांचे के साथ आज हमारा राज्य दूर-दराज़ के इलाकों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ रहा है। डबल इंजन सरकार के दम पर हम आने वाले वर्षों में उत्तराखण्ड के दूरस्थ क्षेत्रों तक रेल पहुँचाने और “लास्ट माइल कनेक्टिविटी” सुनिश्चित करने के लिए आशान्वित हैं।

58. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण की गयी हैं। यहां कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- कोटद्वार के अन्तर्गत चिल्लरखाल-सिगड्डी-कोटद्वार-पाखरो मोटर मार्ग (1-12 किलोमीटर) का सुदृढीकरण पूर्ण किया गया है। इस योजना के पूर्ण होने से सिगड्डी से किशनपुर-झण्डीचौड़- हल्दूखाता-मोटाढांग -दुर्गापुरी-निम्बूचौड एवं कोटद्वार की लगभग 80 हजार की आबादी को सुरक्षित एवं सुगम यातायात की सुविधा प्राप्त हो रही है।
- मोटाढांक के निकट मालुनी नदी पर 325 मीटर सेतु और खोह नदी पर सुरक्षात्मक कार्य भी संपन्न हो चुके हैं। सेतु के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षात्मक कार्य पूर्ण होने से स्थानीय निवासियों तथा सिद्धबली मंदिर को आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित यातायात का लाभ प्राप्त हो रहा है।
- चमोली में जुम्मा से द्रोणागिरी तक 16 किलोमीटर मार्ग और सेतु का निर्माण पूर्ण किया गया है। पोखरी-कर्णप्रयाग मार्ग का सुधारीकरण पूरा किया गया, जो चारधाम यात्रा का वैकल्पिक मार्ग है। मार्ग एवं सेतु निर्माण कार्य पूर्ण होने से दूरस्थ पर्वतीय एवं सीमान्त जनजाति क्षेत्र को सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त हुई है।
- भवाली बाईपास (पार्ट-1) में शिप्रा नदी पर 30 मीटर लंबे सेतु का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जो कैंची धाम में लगने वाले जाम से मुक्ति दिलाएगा।
- मंच-तामली मार्ग और धुनाघाट-रीठा-तलाड़ी मार्ग के सुधारीकरण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। रानीबाग-भीमताल-पंचेश्वर मार्ग का सुधारीकरण पूर्ण हुआ है।
- सितारगंज में शक्तिफार्म-पडागांव और नकुलिया मार्गों का सुदृढीकरण पूरा कर लिया गया है।

59. लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं गतिमान हैं। इस क्रम में, ऋषिकेश में लक्ष्मणझूला के पास 132.30 मीटर लंबे बजरंग सेतु, अल्मोड़ा में एनएच-109 से नए कलेक्ट्रेट और मेडिकल कॉलेज तक मार्ग का चौड़ीकरण, बाजपुर में जैतपुर-धनौरी मार्ग का सुधारीकरण और ऊधमसिंह नगर में नगला-किच्छा

मार्ग को 4-लेन में बदलने का कार्य, गदरपुर-दिनेशपुर-हल्द्वानी मार्ग का निर्माण, चमोली में नंदप्रयाग-नंदानगर मार्ग और थराली-देवाल-वाण मार्ग का सुदृढीकरण कार्य उल्लेखनीय है।

- बेतालघाट (नैनीताल) में दूनीखाल से रातीघाट मार्ग पर कटान का कार्य पूर्ण हो चुका है और दीवारों/कलवर्ट का कार्य प्रगति पर है।
- पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर में गंगा नदी पर 150 मीटर लंबे सिंगटाली सेतु का बहुप्रतीक्षित पुल के निर्माण की प्रक्रिया भी गतिमान है।
- हमारी सरकार द्वारा न केवल सड़कों के नवनिर्माण अपितु विद्यमान सड़कों को गड्ढा मुक्त किये जाने और सुरक्षित बनाये जाने को शीर्ष प्राथमिकता दी गयी है। इसी क्रम में गड्ढा मुक्त सड़क एवं अन्य कार्य योजना के अन्तर्गत रूपये चार सौ करोड़ (रु0 400.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए रूपये पच्चीस करोड़ (रु0 25.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में लगभग रूपये दो हजार पांच सौ एक करोड़ इक्यान्वे लाख (रु0 2501.91 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

60. गांवों की कनेक्टिविटी के लिए पी0एम0जी0एस0वाई योजना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। पी0एम0जी0एस0वाई योजना के अन्तर्गत पूंजीगत मद में रूपये एक हजार पचास करोड़ (रु0 1050.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

61. भौगोलिक परिस्थितियों के कारण हमने एयर कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी है। उत्तराखण्ड सिविल एविएशन डेवलेपमेंट अथॉरिटी के तत्वावधान में हवाई मार्ग यातायात आवागमन को सुगम बनाने के लिए हम सतत प्रयत्नशील हैं।

- इसी क्रम में सहस्त्रधारा, श्रीनगर, गौचर, चिन्यालीसौड़, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा मुनस्यारी में हेलीपोर्ट का संचालन एवं विकास किया गया है।
- इसके अतिरिक्त, त्रियुगीनारायण मंदिर, मसूरी, रामनगर, बागेश्वर एवं हरिद्वार में हेलीपोर्ट निर्माण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- पंतनगर एयरपोर्ट को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकसित किये जाने के क्रम में 524 एकड़ भूमि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया को हस्तांतरित की जा चुकी है।
- पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के सुदृढीकरण का कार्य किया गया है। यह अनुकूल उपयोग में लिये जाने हेतु एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया को हस्तांतरित कर दिया है।
- गौचर एवं चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टियों को भारतीय वायुसेना को हस्तांतरित किये जाने हेतु माननीय मंत्रीमण्डल द्वारा सहमति दे दी गयी है।
- केदारनाथ शटल सेवा को सुदृढ एवं सुरक्षित बनाये जाने के अतिरिक्त गौचर—बद्रीनाथ शटल सेवा को भी आगामी चारधाम यात्रा में आरम्भ किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
- संचालित फिक्स्ड—विंग रूटों के अंतर्गत देहरादून, पंतनगर व पिथौरागढ़ से हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार पर कार्य किया जा रहा है।
- नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में लगभग रूपये बावन करोड़ पचास लाख (रु० 52.50 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

62. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाया है, ताकि उद्योग लगे और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा हो। सरल नियम, सिंगल विंडो क्लियरेंस और पारदर्शी नीति के जरिए हमने उद्यमियों का विश्वास बढ़ाया है।

63. अध्यक्ष जी, उत्तराखंड ने हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी अग्रणी कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने के लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। हिमालयी पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखते हुए विकास करना, हमारी प्राथमिकता है।

64. यू0जे0वी0एन0एल0 के तत्वावधान में विगत 4 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण की गयी है। यहां कुछ योजनाओं का मैं उल्लेख कर रहा हूँ:-

- 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना
- 15 मेगावाट की मदमहेश्वर परियोजना
- 5 मेगावाट की सुरिनगाड परियोजना
- 4.5 मेगावाट की कालीगंगा-द्वितीय
- 90 मेगावाट की तिलोथ परियोजना का रिनोवेशन एण्ड मॉडर्ननाइजेशन
- 51 मेगावाट की ढालीपुर परियोजना का रिनोवेशन एण्ड मॉडर्ननाइजेशन

इन योजनाओं के पूर्ण होने से संबंधित परियोजना क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है।

65. जल विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में एस0जे0वी0एन0 द्वारा 60 मेगावाट की नैटवार मौरी तथा टी0एच0डी0सी0 इण्डिया लि0 द्वारा 750 मेगावाट की टिहरी पम्प स्टोरेज प्लांट भी इस अवधि में पूर्ण हुयी हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने से स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हुआ है तथा एस0जे0वी0एन0 द्वारा विकसित 60 मेगावाट परियोजना के सापेक्ष 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत राज्य को प्राप्त हो रही है।

66. अध्यक्ष जी, उरेडा के तत्वावधान में स्वरोजगार और उद्यमिता विकास के दृष्टिगत 250 मेगावाट के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चलाई गयी है।

इससे लगभग 3500 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में सुधार हो रहा है।

- अब तक कुल 137 मेगावाट क्षमता की 746 परियोजनायें स्थापित की जा चुकी हैं। मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार राज्य में 327 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना की गयी थी जो कि वर्तमान में कुल 1027 मेगावाट हो गयी है। विगत वर्षों में 700 मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर ऊर्जा की स्थापना की जा चुकी है।

67. पिटकुल के तत्वावधान में विगत 4 वर्षों में पूर्ण की गयी लाईनों के विवरणों का मैं यहां उल्लेख कर रहा हूँ:-

- 132 किलोवोल्ट की पदार्था से चीला पारेषण लाईन,
- 220 किलोवोल्ट की जाफरपुर-टी0एस0एस0 रुद्रपुर रेलवे पारेषण लाईन,
- 132 किलोवोल्ट की लक्सर-कैवेन्डिश लाईन,
- 132 किलोवोल्ट की डबल सर्किट काशीपुर- बाजपुर लाईन द्वितीय सर्किट लाईन,
- 220 किलोवोल्ट की बरम- जौलजीवी पारेषण लाईन तथा 132 किलोवोल्ट की बिंदाल-पुरूकुल लाईन।

68. अध्यक्ष जी, यह भी अवगत कराना है कि आगामी वित्तीय वर्ष में पिटकुल के तत्वावधान में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं पूर्ण होने की दिशा में अग्रसर है। मैं यहां कुछ योजनाओं का उल्लेख कर रहा हूँ:-

- 220 किलोवोल्ट की जी0आई0एस0 उपसंस्थान, सेलाकुई, देहरादून
- सेलाकुई उपसंस्थान पर 220 किलोवोल्ट की खोदरी-झाझरा लिलो लाईन
- 132 किलोवोल्ट की जी0आई0एस0 उपसंस्थान, आराघर
- आराघर उपसंस्थान पर 132 किलोवोल्ट माजरा-लालतप्पड़ लिलो लाईन
- 132 किलोवोल्ट जी0आई0एस0 उपसंस्थान, धौलाखेड़ा

- धौलाखेड़ा उपसंस्थान पर 132 किलोवोल्ट काठगोदाम–रूद्रपुर लिलो लाईन
- 132 किलोवोल्ट उपसंस्थान, खटीमा
- खटीमा उपसंस्थान पर 132 किलोवोल्ट खटीमा– सितारगंज लिलो लाईन

69. अध्यक्ष जी, ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रूपये एक हजार छः सौ नौ करोड़ तैतालीस लाख (रू0 1609.43 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

70. अध्यक्ष जी, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के आधारभूत ढांचे के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने और पी0पी0पी0 परियोजनाओं को विकसित करने हेतु वर्ष 2023 में उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (यू0आई0आई0डी0बी0) का गठन किया गया है। यू0आई0आई0डी0बी0 द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के माध्यम से शहरी जल निकासी की बेहतर सुविधाएं, पर्यटकों के लिए उच्च आधारभूत सुविधाएं, सुरक्षित व व्यवस्थित यातायात तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर प्रशस्त होंगे।

- यू0आई0आई0डी0बी0 द्वारा अपनी स्थापना से आतिथि तक अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं यथा गढ़वाल मण्डल में हरिद्वार गंगा कोरिडोर एवं ऋषिकेश गंगा कोरिडोर आरम्भ की गयी हैं और कुमाँऊ मण्डल में शारदा रिवर फ्रंट मास्टर प्लॉन परियोजना क्रियान्वित की जा रही हैं।
- हरिद्वार गंगा कोरिडोर के अन्तर्गत रोडिबेलवाला, एडमिन रोड निर्माण, सती कुण्ड पुर्नविकास एवं हरकी पैड़ी पुनरुज्जीवन योजना, ऋषिकेश गंगा कोरिडोर के अन्तर्गत त्रिवेणी घाट का विकास, चन्द्रभागा पैदल पुल का निर्माण योजना तथा शारदा रिवर फ्रंट परियोजना के अन्तर्गत शारदाघाट पुर्नविकास योजना, किरोड़नाला योजना व सिटी ड्रेनेज योजना क्रियान्वित की जा रही हैं।

- ऋषिकेश के रिवर राफिटिंग साहसिक पर्यटन को वैश्विक स्तर का बनाने के लिए आईकोनिक सिटी ऋषिकेश राफिटिंग बेस स्टेशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- गढ़वाल मण्डल में श्रीनगर स्थित बेलकेदार एवं बेलकण्डी मार्गक्षेत्र में “विशेष आध्यात्मिक-आर्थिक जोन” (स्पेशल स्पिचुअल-इकॉनामिक जोन) स्थापित किया जा रहा है।

71. अध्यक्ष जी, अर्थव्यवस्था का विकास गाँव और शहर दोनों के विकास से होता है। यह बजट गाँव के लिए स्वावलंबन और शहर के लिए आधुनिकता की दोहरी रणनीति लेकर आया है।

इसी क्रम में अब “संतुलन” (SANTULAN) के पांचवे एल्फाबेट “U” अर्थात् उन्नत शहर एवं गाँव के विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

- ग्राम्य सशक्तिकरण के लिए किये गये समग्र प्रयासों को अंग्रेजी भाषा के संक्षिप्ताक्षर **K-** कौशल विकास, **E-** इकालॉजी संवर्द्धन, **D-** धरोहर संरक्षण, **A-** अवसंरचना निर्माण और **R-** से रिवर्स माइग्रेशन से निर्मित “केदार” (**KEDAR**) से समझा जा सकता है।
- इस प्रकार निर्मित परिवेश से गाँवों में आर्थिकी का विस्तार हो रहा है, लोग अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं और यह परिवर्तन ग्राम्य जीवन में एक नये परिवेश—मंगलकारी (**M**), अवसरयुक्त (**A**) नवोन्मेशी (**N**), आध्यात्मिक (**A**) और सांस्कृतिक गतिविधियों (**S**) अर्थात् “मानस” (**MANAS**) के लिए सशक्त प्रेरणा है।
- हमारा विश्वास है “गाँव मजबूत, उत्तराखंड मजबूत।” ग्राम-स्तरीय अवसंरचना व पंचायतों को सशक्त बनाने के दृष्टिकोण से विभिन्न विभागों यथा ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य

विभाग, प्राइमरी शिक्षा विभाग आदि के अन्तर्गत संचालित योजनाएं तथा अवसंरचनायें उल्लेखनीय है।

- "कनेक्टेड विलेज-कनेक्टेड मार्केट" की अवधारणा के तहत राज्य के दूरस्थ और सीमांत गाँवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं डिजिटल-भुगतान आदि सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि पलायन पर रोक लगे और गाँवों में भी सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध हों।
- ग्रामीण आजीविका मिशन, आजीविका सहकारी समितियाँ, दुग्ध सहकारी संघ, इन सबको एक मज़बूत श्रृंखला की तरह जोड़ा जा रहा है। उद्यान, दुग्ध, पशुपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन और रेशम विकास आदि के सुव्यवस्थित विस्तार के साथ हमारे गाँव अब रोज़गार सृजन के केन्द्र बन रहे हैं।
- स्वयं-सहायता समूहों, दुग्ध समितियों, महिला समूहों और किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से ग्राम-स्तर पर लघु-उद्योग, पैकेजिंग, मूल्य-संवर्धन और स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।
- वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अन्तर्गत 51 सीमांत गांवों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इस बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हेतु रूपये चालीस करोड़ (रू0 40.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।

72. विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान, परिसंपत्तियों के निर्माण और आजीविका से जुड़े कार्यों के माध्यम से स्थायी आय वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया है। यहाँ अधिकार दया पर नहीं, गारंटी और सम्मान के साथ दिए जा रहे हैं। इस बजट में वीबी-जी राम जी (VB-G RAM G) हेतु समग्र रूप से लगभग रूपये सात सौ पांच करोड़ पच्चीस लाख (रू0 705.25 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

**73. अध्यक्ष जी,** जल, जंगल और ज़मीन केवल संसाधन नहीं, अपितु उत्तराखण्ड की जीवन-रेखा हैं। इस बजट में हमने पेयजल, सिंचाई, स्रोत-संरक्षण, भू-जल पुनर्भरण, वॉटर-शेड के विकास के संकल्प के साथ योजनाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया है।

**74. ग्रामीण विकास विभाग** के अन्तर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रूपये एक हजार छः सौ बयालीस करोड़ बीस लाख (रु0 1642.20 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

**75. अध्यक्ष जी,** शहरी विकास किसी भी राज्य की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। इसलिए सुव्यवस्थित योजना और प्रबंधन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएँ, पेयजल, स्वच्छता, स्मार्ट मोबिलिटी, और आवास जैसी सेवाएँ उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है।

- शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान के लिए हमने सुनियोजित तरीके से सम्पूर्ण राज्य में विभिन्न स्थानों पर 196 वाहन पार्किंग स्थलों का चयन किया है, जिसमें सरफेस पार्किंग की 66, मल्टीलेवल कार पार्किंग की 112, ऑटोमेटेड कार पार्किंग की 09 तथा टनल पार्किंग हेतु 09 स्थान चिन्हित किये गये हैं।
- 196 स्थानों में से 150 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर ली गयी है, जिसमें लगभग 618 करोड़ की 114 परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है। विकास प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से लगभग 296 करोड़ की 11 परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है।
- इस बजट में आवास विकास विभाग के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि हेतु रूपये एक सौ तीस करोड़ (रु0 130.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

76. राज्य में “अमृत मिशन” के तहत बुनियादी शहरी सेवाएं जैसे सड़कें, जल आपूर्ति और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। हमारे द्वारा शहरों में एफोडेबल हाउसिंग, स्वच्छ जल, सार्वजनिक परिवहन, वेस्ट मैनेजमेंट, हरित क्षेत्र और डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

77. राज्य पोषित योजना के अन्तर्गत चारधाम मार्ग में बाड़ाहाट (उत्तरकाशी), आदिकैलाश मार्ग में पिथौरागढ़ तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण (03 नगर निकायों) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

78. स्वच्छ भारत मिशन फेज-2 के अन्तर्गत पौड़ी, सतपुली, चिन्यालीसौड़, बड़कोट, पुरोला, घनसाली, चमियाला, धारचूला, जसपुर, पिथौरागढ़ की डी0पी0आर0 तैयार की गयी है।

- प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 (शहरी) के अन्तर्गत 2,355 बी0एल0सी0 आवासों का निर्माण कराया जा रहा है। आगामी वर्ष हेतु 4 हजार आवास प्रस्तावित हैं।
- नगरीय क्षेत्रों में समुचित पेयजल और स्वच्छता व्यवस्थाओं के विकास हेतु से राज्य के देहरादून, विकासनगर, हल्द्वानी, कोटद्वार, चम्पावत, टनकपुर, किच्छा, नगरों में ए0डी0बी0 पोषित तीन भिन्न परियोजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति और वितरण प्रणाली, सीवरेज विकास, ड्रेनेज तथा सड़क निर्माण इत्यादि कार्य प्रगति पर हैं। इन तीन योजनाओं के लिए पूंजीगत मद में रूपये छः सौ बावन करोड़ (रु0 652.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- नगरीय अवस्थापना के सुदृढीकरण हेतु रूपये साठ करोड़ (रु0 60.00 करोड़) का प्रावधान किया जा रहा है।
- आवास विभाग के अन्तर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रूपये दो सौ इक्यानवे करोड़ (रु0 291.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

- सरयू एवं अन्य रिवर फ्रन्ट परियोजनाओं के विकास हेतु रूपये दस करोड़ (रू0 10.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत समग्र रूप से पूंजीगत मद में रूपये एक हजार चार सौ एक करोड़ पिचासी लाख (रू0 1401.85 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।
- अध्यक्ष जी, 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के क्रम मे हम इस बजट में शहरी निकायों हेतु समग्र रूप से रूपये एक हजार आठ सौ चौदह करोड़ (रू0 1814.00 करोड़) एवं पंचायती राज संस्थाओं हेतु रूपये एक हजार चार सौ इक्यानवे करोड़ (रू0 1491.00 करोड़) का बजट प्रावधान कर रहे हैं।

79. अध्यक्ष जी, जनहित, जन-सहभागिता और सुशासन हमारी कार्य नीति है। हम मानते हैं कि नीतियाँ कागज़ पर नहीं, लोगों के जीवन में दिखने वाले बदलाव से परखी जाती हैं। हमारे लिए सिर्फ योजना बनाना पर्याप्त नहीं, समस्या का वास्तविक समाधान और नागरिक की संतुष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में अब मैं “संतुलन” (SANTULAN) के छठे एल्फाबेट “L” अर्थात् लोक सहभागिता के लिए किये जा रहे प्रयासों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:-

सुशासन हमारे लिए सर्वोपरि है। यह बजट सुशासन के मार्ग को आगे बढ़ाता है, जिसमें शासन की नीति और योजना और व्यय-निर्णय का केंद्र बिंदु सामान्य नागरिक, विशेषकर अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है। हमारा उद्देश्य है कि कोई भी नागरिक अपने अधिकारों से वंचित न रहे और किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए उसे दर-दर नहीं भटकना पड़े।

80. पहली बार “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी जनपदों में न्याय पंचायत स्तर तक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 660 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 5.33 लाख से

अधिक नागरिकों ने सहभागिता की तथा 33 हजार से अधिक जन शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अभियान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों सहित प्रदेशभर के नागरिकों को घर के पास ही सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त हुआ है।

सरकार का दायित्व केवल नीतियां बनाना नहीं, बल्कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक उसका लाभ पहुँचाना है। "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" इसी सोच का परिणाम है।

81. अध्यक्ष जी, बजट एक माध्यम है जनता की आंकाक्षाओं को साकार करने का। इसलिए हमने बजट में जन-सहभागिता को और सुदृढ़ किया है। हम बजट निर्माण में न केवल जनता के सुझाव आमंत्रित करते हैं अपितु स्वयं जनता के बीच में जाते हैं। इसी क्रम में कुर्ना मण्डल में बनबसा तथा गढ़वाल मण्डल में पौड़ी में बजट-पूर्व संवाद कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

82. लोक सहभागिता बढ़ाने के लिए हमने विभिन्न विभागों के अन्तर्गत टैक्नोलाजी को बढ़ावा दिया है। इसी क्रम में राजस्व विभाग द्वारा 06 पोर्टल 10 जनवरी 2026 को लान्च किये गये हैं:-

- खतौनी ऑनलाइन प्राप्त करने हेतु ई-भूलेख।
- सजरा मानचित्र ऑनलाइन देखने हेतु ई-भूनक्शा।
- कृषि एवं कृषि से संबंधित गतिविधि के लिए ऋण प्राप्त करने हेतु ई-एग्रीलोन।
- प्रदेश में निवेश आदि के दृष्टिगत भूमि क्रय की अनुमति प्राप्त करने हेतु ई-भूअनुमति।
- खतौनी में खातेदार एवं सह खातेदार के अंश का निर्धारण हेतु ई-भूलेख अंश।

- राजस्व वसूली हेतु ई-आर0सी0एस0 ।
- राजस्व न्यायालयों को पूर्णतः ऑनलाइन एवं पेपरलेस बनाये जाने हेतु ई-आर0सी0एम0एस0 की कार्यवाही गतिमान है ।

83. अध्यक्ष जी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन सेवाएँ और पारदर्शी प्रक्रियाएँ केवल फाइलों की गति नहीं बढ़ा रहे, बल्कि आम नागरिक के आत्मसम्मान को मजबूत कर रहे हैं। अब दुर्गम क्षेत्र का व्यक्ति भी महसूस करता है कि सरकार उसके गाँव की चौपाल और उसके मोबाइल दोनों पर एक साथ मौजूद है।

84. अध्यक्ष जी, अच्छे शासन की कसौटी वही समाज होता है, जहाँ आम नागरिक बिना डर-भय के अपनी बात कह सके और उसे विश्वास हो कि सरकार उसकी शिकायत पर निष्पक्ष कार्यवाही करेगी। “मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905”, का प्रभावी क्रियान्वयन नई सोच का प्रतीक है। नागरिक टोल-फ्री कॉल, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं, जिससे सरकार और जनता के बीच संवाद, जवाबदेही और विश्वास का नया मॉडल विकसित हुआ है।

85. “भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए टोल-फ्री नंबर 1064” के प्रभावी क्रियान्वयन से हमने यह संदेश दिया है कि अब किसी भी स्तर पर होने वाली अनियमितता, रिश्वतखोरी या दुरुपयोग पर चुप रहने और कार्यालयों के चक्कर काटने की मजबूरी नहीं है। टोल-फ्री नंबर 1064 का प्रभावी क्रियान्वयन “भ्रष्टाचार-मुक्त उत्तराखण्ड” के संकल्प को नागरिक सहभागिता के साथ जोड़ता है।

86. अध्यक्ष जी, “संतुलन” के सातवें एल्फाबेट A अर्थात् आर्थिक शक्ति के संबंध में अवगत कराना है कि इकॉनामी एवं इकॉलाजी के मध्य संतुलन बनाते हुए, कृषि, उद्योग एवं पर्यटन तीनों ग्रोथ ड्राइवर्स को समुचित प्राथमिकता देते हुए, विकसित भारत के लक्ष्यों के साथ उत्तराखण्ड के विकास की रणनीति को सम्बद्ध करते हुए आर्थिक शक्ति के रूप में उत्तराखण्ड को स्थापित करना हमारा परम ध्येय है।

- इसी क्रम में मानव पूंजी में निवेश, क्षमता संवर्धन, पूंजीगत व्यय में वृद्धि, निर्वाध एवं सुरक्षित संयोजकता एवं प्रौद्योगिकी आधारित विकास और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को एकीकृत दृष्टि के साथ विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।
- हम प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करते हुए नए अवसरों का लाभ प्रदेश को दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। स्थानीय संसाधनों, उद्यमिता और नवाचार की शक्ति से एक आशापूर्ण परिवेश निर्मित हो रहा है।

87. अध्यक्ष जी, सुशासन हमारा जीवन-मंत्र है। कुशलता, जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता हमारी प्रशासनिक व्यवस्था के मार्गदर्शक हैं। ई-गवर्नेंस का प्रभावी क्रियान्वयन “शासन को सेवा” में बदल रहा है। पारदर्शी व्यवस्था, तकनीक आधारित शासन, वित्तीय सुप्रबन्धन और सर्वस्पर्शी विकास के माध्यम से जनता का विश्वास शासन प्रणाली में लगातार बढ़ रहा है।

88. इसी क्रम में “संतुलन” (SANTULAN) के आठवें एल्फाबेट “N” अर्थात् न्यायपूर्ण व्यवस्था की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ:-

- न्यायपूर्ण व्यवस्था के लिए आवश्यक है कि कानून समान रूप से लागू हो, निर्णय पूर्वाग्रह रहित हो और व्यक्ति अपनी सामाजिक या आर्थिक स्थिति के कारण न्याय से वंचित न रहे। हमने अनेक योजनाओं के माध्यम से न्याय, गृह, समाज कल्याण, जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण सहित अन्य विभागों में आवश्यक प्रावधान किये हैं।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास और आजीविका आदि के क्षेत्र में सामाजिक न्याय को आर्थिक अवसर में बदलने का प्रभावी साधन है। शिक्षा एवं कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण की

योजनाओं आदि को ध्यान में रखकर किये जा रहे बजट प्रावधान इस दिशा में सशक्त पहल हैं। इस बजट में यथास्थान ऐसे अनेक प्रावधान किये जा रहे हैं।

89. देवभूमि उत्तराखण्ड के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए हम कृत-संकल्प है। अतिक्रमण-मुक्त उत्तराखण्ड के लिए नदियों, नालों, तालाबों, सरकारी-और वन-भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व, वन, सिंचाई और शहरी विकास विभागों की संयुक्त कार्ययोजना लागू है। राज्य की सरकारी भूमि, अतिक्रमण-मुक्त करने की दिशा में हमने महत्वपूर्ण प्रगति की है।

90. देवभूमि परिवार योजना के अन्तर्गत राज्य का एक एकीकृत, व्यापक एवं गतिशील परिवार आधारित डाटा बेस का निर्माण किया जा रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष में इस योजना को लागू किया जायेगा। इस बजट में देवभूमि परिवार योजना के अन्तर्गत लगभग रूपये दस करोड़ सत्रह लाख (रु0 10.17 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

91. हमारा ध्येय है कि उत्तराखण्ड ऐसा राज्य बने:

*जहाँ नागरिक सिर ऊँचा रखकर जी सकें,  
ज्ञान, अवसर तथा न्याय सबके लिए मुक्त और सहज हो,  
जहाँ मानवीय संवेदनाओं का दिया अखण्ड जलता हो,  
और हृदय वसुधैव कुटुम्बकम भाव से धड़कता हो।*

यह बजट रोज़गार-परक विकास को नई दिशा देने वाला है। हमारा लक्ष्य है कि युवाओं को अपने गाँव, अपने ज़िले और अपने राज्य में सम्मानजनक रोज़गार और स्वरोज़गार के अवसर मिले, ताकि पलायन रुके और "रिवर्स माइग्रेशन" को बढ़ावा मिले।

92. रोज़गार-आधारित विकास के लिए हमारा संकल्प है कि "सिर्फ रोज़गार नहीं, बल्कि रोज़गार के अवसरों की श्रृंखला तैयार करनी है। इस बजट में कौशल विकास,

उद्योग, एम0एस0एम0ई0, पर्यटन, कृषि-आधारित इकाइयाँ, और सेवा क्षेत्र को इस तरह प्रोत्साहित किया गया है कि नए उद्यम सृजित हों, पुराने उद्यमों को नई रफ्तार मिले और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हों।

93. राज्य की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए उत्तराखंड कौशल विकास मिशन, मुख्यमंत्री रोजगार योजना 2.0, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्वतीय पर्यटन रोजगार योजना, एमएसएमई और स्टार्टअप नीतियों आदि कार्यक्रमों को इस बजट में और सुदृढ़ किया जा रहा है।

94. अध्यक्ष जी, विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से हमने उद्यमिता विकास के अनुरूप परिवेश का निर्माण किया है। अर्थव्यवस्था में युवा, उद्यमी, प्रगतिशील कृषक आदि के सशक्त योगदान के लिए राह प्रशस्त है। इसका परिणाम यह देखने में आ रहा है कि “ब्रेन-ड्रेन” अब “ब्रेन-गेन” में बदल रहा है। अनेक उद्यमशील प्रवासी अपनी जड़ों से जुड़ रहे हैं।

*उद्यमशीलता के परिवेश की पहचान यही होती है,  
हौसलों के साथ सरकार खड़ी होती है।*

95. अध्यक्ष जी, विकसित उत्तराखंड की संकल्प सिद्धि के लिए संकल्प मॉडल के उपरान्त रोजगार योजनाओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ:-

- रोजगार, सृजन एवं उद्यमिता विकास के दृष्टिगत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना (रु0 10 करोड़), मुख्यमंत्री जनजाति रोजगार उत्कर्ष योजना एवं मुख्यमंत्री स्वावलंबी बंदी कौशल विकास योजना प्रस्तावित कर रहे हैं।
- नई मांग के माध्यम से ही आई0टी0आई0 उन्नयन हेतु पी0एम0सेतु के अन्तर्गत समग्र रूप से रूपये बीस करोड़ (रु0 20.00 करोड़) एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस एवं क्षमता विकास के अन्तर्गत रूपये अस्सी करोड़ (रु0 80.00 करोड़) का बजट प्रावधान किया जा रहा है।

96. आदरणीय अध्यक्ष जी, यह बजट केवल संख्याओं, योजनाओं और घोषणाओं का संग्रह नहीं, अपितु सवा करोड़ नागरिकों का साझा 'विजन' है।

यह बजट "विकास व विरासत, संस्कृति व आधुनिकता, आध्यात्म व विज्ञान" का संतुलित संगम है। हम वित्तीय अनुशासन, समावेशी विकास, समग्र विकास, पर्यावरण संरक्षण और सहभागी शासन के आधार स्तम्भों पर 'समस्या-समाधान और निस्तारीकरण' के मूल मंत्र के साथ "विकसित उत्तराखण्ड" की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से देवभूमि की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सभी क्षेत्रों को समान अवसरों के साथ आगे बढ़ाने तथा आर्थिक समृद्धि के केंद्र के साथ-साथ पर्यावरणीय संतुलन को भी ध्यान में रखते हुए विकास की यात्रा पर निरंतर आगे बढ़ेंगे।

हम उत्तराखण्ड की ऊर्जावान युवाशक्ति, प्राकृतिक संपदा और आध्यात्मिक विरासत को समन्वित कर नए रोजगार, नए अवसर और नई उम्मीदों का सृजन करेंगे।

यह बजट "संकल्प से शिखर तक" की सुचारु यात्रा के साथ विकसित भारत की अग्रिम पंक्ति में गर्व से खड़ा होने का एक संकल्प है।

आदरणीय अध्यक्ष जी,

विश्वविख्यात लेखक विक्टर ह्यूगो के शब्दों को उद्धरित कर रहा हूँ,

"जिस विचार का समय आ गया हो उसे कोई रोक नहीं सकता"

तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने का विचार परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मानस में श्री केदारनाथ के पवित्र प्रांगण में आया। तब से लेकर आज तक हम अनेक सामाजिक, आर्थिक संकेतकों में तीव्र प्रगति की ओर अग्रसर हैं।

*तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के,  
पुण्य विचार को चरितार्थ करने के लिए,  
सशक्त उत्तराखण्ड के निर्माण के लिए,  
विकसित उत्तराखण्ड बनाने के विकल्प रहित संकल्प के साथ*

मैं, देवभूमि की महान जनशक्ति की सामूहिक ऊर्जा से वित्तीय वर्ष 2026–27 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रहा हूँ:-

वित्तीय वर्ष 2026–27 में कुल प्राप्तियाँ लगभग रूपये एक लाख दस हजार एक सौ तैंतालीस करोड़ तेरह लाख (रु0 1,10,143.13 करोड़) अनुमानित है, जिसमें रूपये सड़सठ हजार पांच सौ पच्चीस करोड़ सतहत्तर लाख (रु0 67,525.77 करोड़) राजस्व प्राप्तियाँ तथा रूपये बयालीस हजार छः सौ सतरह करोड़ पैंतीस लाख (रु0 42,617.35 करोड़) पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं।

वित्तीय वर्ष 2026–27 में राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व रूपये तैंतालीस हजार तीन सौ सत्ताईस करोड़ तैंतालीस लाख (रु0 43,327.43 करोड़) है, जिसमें केन्द्रीय करों में राज्यांश रूपये सतरह हजार चार सौ चौदह करोड़ सतावन लाख (रु0 17,414.57 करोड़) सम्मिलित है।

राज्य के स्वयं के स्रोतों से कुल अनुमानित राजस्व प्राप्ति रूपये इकतीस हजार छः सौ बीस करोड़ तीन लाख (रु0 31,620.03 करोड़) में कर राजस्व रूपये पच्चीस हजार नौ सौ बारह करोड़ छियासी लाख (रु0 25,912.86 करोड़) तथा करेत्तर राजस्व रूपये पांच हजार सात सौ सात करोड़ सतरह लाख (रु0 5,707.17 करोड़) अनुमानित है।

व्यय:

वर्ष 2026-27 में ऋणों के प्रतिदान (W.M.A./अर्थोपाय अग्रिम सहित) पर रूपये अट्ठाईस हजार एक सौ साठ करोड़ तिरेसठ लाख (रू0 28,160.63 करोड़), ब्याज की अदायगी के रूप में रूपये सात हजार नौ सौ उनतीस करोड़ चालीस लाख (रू0 7,929.40 करोड़), राज्य कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि पर लगभग रूपये उन्नीस हजार एक सौ चौहत्तर करोड़ सतानवे लाख (रू0 19,174.97 करोड़), सहायता प्राप्त शिक्षण व अन्य संस्थाओं एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तों के रूप में लगभग रूपये एक हजार चार सौ उनासी करोड़ नौ लाख (रू0 1,479.09 करोड़), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों के रूप में रूपये ग्यारह हजार एक सौ सैंतीस करोड़ (रू0 11,137.00 करोड़), व्यय अनुमानित है।

वर्ष 2026-27 में कुल व्यय रूपये एक लाख ग्यारह हजार सात सौ तीन करोड़ इक्कीस लाख (रू0 1,11,703.21 करोड़) अनुमानित है। कुल अनुमानित व्यय में से रूपये चौसठ हजार नौ सौ नवासी करोड़ चौवालीस लाख (रू0 64,989.44 करोड़) राजस्व लेखे का व्यय है तथा रूपये छियालीस हजार सात सौ तेरह करोड़ सतहत्तर लाख (रू0 46,713.77 करोड़) पूंजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि

वर्ष 2026-27 के बजट में कोई राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है, अपितु रूपये दो हजार पांच सौ छत्तीस करोड़ तैंतीस लाख (रू0 2,536.33 करोड़) का राजस्व अधिशेष (सरप्लस) सम्भावित है। रूपये बारह हजार पांच सौ उन्यासी करोड़ सत्तर लाख (रू0 12,579.70 करोड़) का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.94 प्रतिशत है। यह एफ0आर0बी0एम0 एक्ट में निर्दिष्ट सीमा के अन्तर्गत है।

वर्ष 2026–27 के अनुमानित प्रारम्भिक शेष रूपये सात सौ तिरेपन करोड़ सत्तावन लाख (रू0 753.57 करोड़) धनात्मक तथा वर्ष का अन्तिम शेष रूपये अट्ठारह करोड़ अड़तालीस लाख (रू0 18.48 करोड़) धनात्मक रहना अनुमानित है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं, मंत्रीमण्डल के अपने सहयोगियों के सहयोग के लिए आभार प्रकट करता हूँ। बजट निर्माण में बजट-पूर्व संवाद में हमको देवतुल्य जनता से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए थे। मैं इस अवसर पर बजट निर्माण में सहभागिता हेतु देवतुल्य जनता को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट तैयार करने में जो सहायता मुझे दी है, उसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं महालेखाकार, उत्तराखण्ड का आभारी हूँ। मैं, राजकीय मुद्रणालय रुड़की तथा एन0आई0सी0 के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ।

*विरासत है, धरोहर है,  
नवाचार की पैमाइश है,  
विकसित उत्तराखण्ड बनाने के लिए,  
बजट में अजमाइश है।  
शिखर पर रहे देवभूमि,  
बस इतनी सी ख्वाहिश है,  
बस इतनी सी ख्वाहिश है!*

इन्हीं शब्दों के साथ, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं वित्तीय वर्ष 2026–27 का आय-व्ययक प्रस्तुत करता हूँ:-

फाल्गुन 18, शक सम्वत् 1947

तदनुसार

09 मार्च, 2026